रणजीत टाइम्स

इंदौर

बुधवार , 1 अप्रैल, 2026

वर्ष 02 | अंक 83 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

गुजरात में विकास का महाअभियान

पीएम ने 20 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया शुभारंभ

अहमदाबाद। गुजरात आज एक बड़े विकासात्मक बदलाव का साक्षी बना, जब प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राज्य को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की विशाल सौगात दी। इस दौरान उन्होंने न केवल कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बल्कि अनेक नई योजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और शहरी सुविधाओं को नई गति मिलने जा रही है। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रही, जिसे करीब 5,100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि गुजरात के भविष्य की रफ्तार का प्रतीक माना जा रहा है। इससे अहमदाबाद और धोलेरा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट राज्य को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

इसके साथ ही गांधीनगर के कोबा में 'सम्राट संप्रति म्यूजियम' का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री ने गुजरात की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देने का प्रयास किया। वहीं साणंद में सीएएनएस

सेमीकंडक्टर ओएसएटी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन देश को टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना आने वाले समय में भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिला सकती है। शाम के कार्यक्रमों में वाव-थराद क्षेत्र के नाणी गांव से प्रधानमंत्री ने उत्तर गुजरात के विकास को नई रफ्तार देने वाली कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को कम करना और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना है। शहरी विकास के मोर्चे पर भी बड़ा निवेश देखने को मिला। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 4,640 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की गईं, जबकि गांधीनगर और अन्य विकास प्राधिकरणों ने भी सैकड़ों करोड़ रुपये की योजनाओं को गति दी। कुल मिलाकर 5,295 करोड़ रुपये से अधिक की 44 शहरी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें सड़क, जल आपूर्ति, ड्रेनेज और स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्य शामिल हैं। इतिहास और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वडनगर में 'हेरिटेज टाउन डेवलपमेंट एंड रोड ब्यूटीफिकेशन' परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। इस योजना के तहत हाटकेश्वर मंदिर और म्यूजिक म्यूजियम जैसे प्रमुख स्थलों को आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक सौंदर्यीकरण के साथ विकसित किया गया है, जिससे पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पाटन में 43 करोड़ रुपये की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया गया, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लाखों लोगों को सुरक्षित एवं तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खेडब्रह्मा से अहमदाबाद के बीच नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो हिम्मतनगर के रास्ते चलेगी। इस नई रेल सेवा से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़

8 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, कई घायल

बिहार के Nalanda जिले में स्थित शीतला मंदिर में मंगलवार को पूजा के दौरान भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ के बीच अचानक अफरा-तफरी फैल गई, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और मंदिर प्रबंधन व प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

हिंदू खतरे में

सियासत का शोर या ज़मीनी सच्चाई?

मुद्दे की जड़ क्या है?

भारत एक बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाला देश है, जहां हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 80% के आसपास है। ऐसे में "खतरे" की बात कई बार लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा अक्सर धार्मिक पहचान और भावनाओं को प्रभावित कर वोट बैंक मजबूत करने के लिए उठाया जाता है।

राजनीति का नजरिया कई राजनीतिक दल और संगठन समय-समय पर यह दावा करते हैं किः

हिंदू संस्कृति पर हमला हो रहा है परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है जनसंख्या संतुलन बदल रहा है इन बयानों का उपयोग अक्सर चुनावी रैलियों और भाषणों में देखा जाता है। जमीनी हकीकत क्या कहती है?

अंतिम सवाल क्या यह मुद्दा जनता की असली समस्याओं

»» बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा-से ध्यान भटकाने का जरिया बन रहा है? या फिर यह एक ऐसी चिंता है जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत है? आपकी राय क्या है? क्या "हिंदू खतरे में" एक सच्चाई है या सिर्फ राजनीति?

सामाजिक शोध और आंकड़ों के अनुसार

»» हिंदू समाज आज भी देश में बहुसंख्यक और प्रभावशाली है धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है मंदिर, त्योहार और परंपराएं खुले रूप से मनाई जाती हैं हालांकि, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर तनाव, धर्मांतरण या सांप्रदायिक घटनाएं जरूर देखने को मिलती हैं, जिन्हें पूरे देश की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है।

देश की राजनीति में "हिंदू खतरे में है" का नारा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है

चुनावी मौसम हो या सामाजिक तनाव, यह मुद्दा बार-बार उभरता है—लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में कोई गंभीर खतरा है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है?

विशेषज्ञों की राय

»» राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है किः"खतरे की भावना अक्सर वास्तविक खतरे से ज्यादा 'धारणा' (Perception) होती है, जिसे बार-बार दोहराकर मजबूत किया जाता है।" "हिंदू खतरे में है"-यह मुद्दा पूरी तरह से काला या सफेद नहीं है।कुछ जगहों पर सामाजिक तनाव वास्तविक हो सकता है लेकिन इसे व्यापक स्तर पर पेश करना अक्सर राजनीतिक लाभ से जुड़ा होता है

चुनाव आयोग के रडार पर ममता?

BJP ने दर्ज कराई शिकायत, रैलियों में दिए बयानों पर बवाल

पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पश्चिम बंगाल इकाई ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय में एक शिकायत सौंपी। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपने चुनावी अभियानों में लोगों को उकसाने, डराने-धमकाने, धमकियां देने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। BJP का कहना है कि ये हरकतें राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन करती हैं।

ममता के खिलाफ बीजेपी की शिकायत

CEO को लिखे एक संयुक्त पत्र में जिसमें BJP के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के लोकसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। पत्र में यह दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के ऐसे भड़काऊ भाषण चल रही चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए एक गंभीर खतरा हैं। ये भाषण MCC, चुनावी कानूनों और आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं।

बीजेपी ने सौंपी भड़काऊ भाषणों की लिस्ट

BJP ने दावा किया है कि उनके भाषणों से यह साफ जाहिर था कि मुख्यमंत्री का एकमात्र मकसद मतदाताओं में डर पैदा करना और उन्हें दबाव में लाना था। यह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए एक खतरा है। इसके बाद, BJP ने ऐसे भाषणों की एक विस्तृत सूची सौंपी है, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान दिए थे।

मूकदर्शक बनकर रह गई बंगाल पुलिस

CEO को लिखे पत्र में कहा गया है, 'मुख्यमंत्री की ऐसी सार्वजनिक धमकियों के कारण ही राज्य पुलिस बल मूकदर्शक बनकर रह गया है, जिसके चलते अपराधी हिंसा करने के लिए और ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि 2021 के पिछले विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने इसी तरह के भाषण दिए थे, जिसके कारण चुनाव से पहले और बाद में हिंसा भड़की थी और पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में अशांति फैल गई थी। मतगणना के बाद, महज 45 दिनों के भीतर ही हमारे 55 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी।'

उचित और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग

पत्र में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से यह भी **आग्रह किया गया है कि वह इन बयानों और घटनाओं का तत्काल संज्ञान ले, MCC के तहत उचित कार्रवाई शुरू करे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के विभिन्न प्रावधानों के तहत उचित और कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे, जिसमें FIR दर्ज करना भी शामिल है। BJP ने ECI से यह भी अनुरोध किया है कि वह मुख्यमंत्री पर चुनावी रैलियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं पर विचार करे।**

लेडी टीआई ने कर दी राज्य मंत्री की फजीहत

श्योपुर में पहले राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी ने मंच पर मौजूद कराहल की महिला टीआई यास्मीन खान को खरी-खोटी सुनाई। फिर टीआई ने माइक अपने हाथ में लेते हुए नेता जी को हाथों-हाथ जवाब दे दिया। हुआ यूं कि राज्य मंत्री सीताराम आदिवासी पनवाड़ा माता मेले में अव्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे थे। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेले में सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कमी रही। कई श्रद्धालुओं को असुविधा हुई। उन्होंने टीआई की ओर इशारा करते हुए कहा- फालतू नाटक नहीं करें। ऐसे टीआई कई चले गए। जातिवाद कर रहे हैं आप। जब से ये टीआई साहब आए हैं, तब से घटनाएं हो रही हैं। कई घटनाएं हो गई हैं। इस पर टीआई यास्मीन खान ने भी मंच से ही कहा- मुझे लगता है कि यहां बैठे एक या दो लोगों को छोड़ दें तो हमसे किसी को कोई शिकायत नहीं रही होगी। अगर किसी को शिकायत है तो अपना हाथ ऊपर कर दें। टीआई ने आगे कहा- हमारे स्टाफ ने सुबह से शाम तक, धूप में, भूखे रहकर ड्यूटी की है। लेकिन अपने पर्सनल हित के लिए, पर्सनल दुश्मनी के लिए पूरे स्टाफ और पूरे पुलिस प्रशासन को दोषी कहना कहीं से भी उचित नहीं है। टीआई ने कहा कि अगर आप पर्सनल हित के लिए सीताराम आदिवासी के कान भरते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। टीआई ने जो कहा, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अब लोग कह रहे हैं कि महिला पुलिस अधिकारी ने भरे मंच से नेता जी की फजीहत कर दी। खरी बात ये है कि अपनी ही पार्टी में सम्मान को तरस रहे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी को भी ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। वे कई बार अपनी ही पार्टी में उपेक्षा और अधिकारियों की अनदेखी की शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में ये वाकया उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है।

प्रमोशन के लिए 18 साल कानूनी लड़ाई, हाईकोर्ट का मरणोपरांत फैसला, देना होगा प्रमोशन और सेलरी डिफ्रेंस

ग्वालियरः कहते हैं न्याय में समय लग सकता है लेकिन मिलता जरूर है और ये बात ग्वालियर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद साबित होती दिखाई दी. यहां 18 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक याचिकाकर्ता को उसके मरणोपरांत उसका हक मिल ही गया. मामला कृषि विभाग के अधिकारी के प्रमोशन का है, जिस पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने अब फैसला उनके हक में दिया है. हाईकोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मृत्यु के बाद भी कर्मचारी के अधिकार खत्म नहीं होते और उनके परिवार को उचित हक मिलना चाहिए।

याचिकाकर्ता की जगह जूनियर को दिया था प्रमोशन- ग्वालियर के रहने वाले राधाकृष्ण शर्मा ने 2008 में ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी और बताया था कि, साल 2002 में वे सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर थे और उनका प्रमोशन होना था लेकिन जब समय आया तो विभाग ने उनकी पदोन्नति रोक दी और उनकी जगह उनके जूनियर को पदोन्नत कर दिया. जिसके खिलाफ उन्होंने 6 साल बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. राधाकृष्ण शर्मा 2009 में सेवानिवृत्त हो गए थे।

'आपराधिक मामले को आधार बनाकर रोका था प्रमोशन' याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट आलोक कटारे ने बताया "राधाकृष्ण शर्मा को 18 नवंबर 1978 को वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था. जब 2002 में नियम अनुसार उनका प्रमोशन होना था तब 01 अप्रैल 2002 को पदोन्नति के लिए बनी लिस्ट में उनका नाम 63वें स्थान पर था लेकिन उनके स्थान पर उनके एक जूनियर को पदोन्नत कर दिया गया और राधाकृष्ण शर्मा की पदोन्नति रोक दी गई. जिसके पीछे वजह बताई गई कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है, बाद में 2005 में इस मामले से याचिकाकर्ता को कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया लेकिन विभाग द्वारा उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया."।

निर्दोष साबित होने के बाद भी नहीं मिला प्रमोशन- राधाकृष्ण शर्मा को जब उनका हक नहीं मिला तो उन्होंने अपने वकील के जरिये 2006 में विभाग को बताया कि उनके ऊपर पदोन्नति रोकने के लिए लगाए गए आरोपों को कोर्ट ऑर्डर के आधार पर खारिज बताया गया. अपना हक मांगने पर भी जब विभाग द्वारा उनकी सुनवाई नहीं हुई तो 2008 में उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और मामले में सुनवाई शुरू हुई. लेकिन जनवरी 2026 में याचिकाकर्ता राधाकृष्ण शर्मा का निधन हो गया. जिसके बाद उनके बेटे ने इस याचिका को आगे बढ़ाया और करीब 18 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला दे दिया। हाईकोर्ट ने फैसले के साथ की तीखी टिप्पणी-वकील आलोक कटारे के मुताबिक ग्वालियर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश शासन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "शासन की गलती की वजह से याचिकाकर्ता राधाकृष्ण शर्मा को उनका प्रमोशन नहीं मिल सका, अगर किसी कर्मचारी की पदोन्नति विभागीय गलती से रोकी जाती है, तो उसे पूरा लाभ मिलना चाहिए. 'नो वर्क-नो पे' का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा. बिना बताए गए एसीआर को पदोन्नति का आधार बनाना कानून के खिलाफ है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. ऐसे में याचिकाकर्ता का प्रमोशन 2002 से दिया जाए और उन्हें प्राप्त सभी देयकों का भुगतान उनके परिवार को किया जाए." कोर्ट ने निर्देश दिया कि राधाकृष्ण शर्मा को 28 अक्टूबर 2002 से पदोन्नत माना जाए और उनके परिवार को एरियर, वेतन और वरिष्ठता का लाभ दिया जाए. मौत के बाद भी कर्मचारी के अधिकार खत्म नहीं होते, और उनके परिवार को उचित हक मिलना चाहिए।

रणजीत टाइम्स

इंदौरः लालाराम नगर में ताला तोड़ी, धमकी और मारपीट- पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल

इंदौर। दो माह बाद भी न्याय नहीं, परिवार ने वरिष्ठ अधिकारियों से लगाई गुहार

इंदौर। लालाराम नगर स्थित मकान नंबर 21 पर 16 दिसंबर 2025 की रात अज्ञात व्यक्तियों ने ताला तोड़कर जबरन प्रवेश किया और वहाँ चौकीदारी कर रहे दशरथ कैथवास को जान से मारने की धमकी दी। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के समय पुलिस की गाड़ी मौके पर मौजूद बताई गई, बावजूद इसके पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला।

घटना की रात-पुलिस मौजूद, फिर भी बेबस रहा परिवार

जब दशरथ कैथवास ने आरोपियों से परिचय पूछा, तो उन्हें धमकी दी गई- "यहाँ दिखाई मत देना, वरना हाथ-पैर तोड़ देंगे।" उस वक्त मौके पर पुलिस वाहन की उपस्थिति के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही खंडवा में मीडिया कार्य से गई रेणु कैथवास ने तत्काल पलासिया थाना प्रभारी और ड्यूटी ऑफिसर संदीप वर्मा को फोन किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसी कोई

सूचना थाने तक नहीं पहुँची।

17 दिसंबर- पीड़ित परिवार ही पहुँचा हिरासत में

अगले दिन जब दशरथ कैथवास सहित परिवार के अन्य सदस्य उक्त संपत्ति पर पहुँचे, तो पुलिस ने पाँच लोगों को- जिनमें दो महिलाएँ भी शामिल थीं-पलासिया थाने ले जाया। घर पर छोटा बच्चा होने के बावजूद महिलाओं को छोड़ने की परिवार की बार-बार की गुज़ारिश अनसुनी रही। वकील के माध्यम से चौकीदारी से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज (रजिस्ट्री) थाना प्रभारी को दिखाए गए, फिर भी तत्काल रिहाई नहीं हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) से हस्तक्षेप के बाद रात करीब 8 बजे महिलाओं को रिहा किया गया, परंतु दशरथ कैथवास, राजू कैथवास और

शुभम कैथवास को हिरासत में रखा गया। परिवार का आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई - "ज़्यादा बोले तो 20 साल के लिए जेल भेज देंगे।"

10,000 रुपये देने के बाद हुई रिहाई-गंभीर आरोप

रेणु कैथवास के इंदौर लौटने पर एक वकील के माध्यम से 10,000 रुपये अदा करने के बाद तीनों व्यक्तियों को रिहा किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि परिवार का कोई भी सदस्य लालाराम नगर, मकान नंबर 21 के पास गया, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

18 दिसंबर-जेसीबी से तोड़फोड़, संपत्ति को नुकसान

18 दिसंबर को उक्त स्थान पर जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ की गई, जिसमें परिवार की यामाहा और अपाचे

मोटरसाइकिल सहित घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। शिकायत लेने से मना, दो माह तक कोई कार्रवाई नहीं परिवार के अनुसार जब वे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुँचे, तो पहले आवेदन लेने से ही मना कर दिया गया। रेणु कैथवास - जो एक समाचार संस्थान में डेस्क इंचार्ज हैं-के साथ जाने पर आवेदन तो स्वीकार किया गया, किंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देने के बाद अब पलासिया थाने से फोन आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है-"तीन-तीन आवेदन आ गए हैं, थाने में उपस्थित हों, अन्यथा लिख देंगे कि आप कार्रवाई नहीं चाहते।"

परिवार के सवाल, जो जवाब माँगते हैं

पीड़ित परिवार ने प्रशासन के समक्ष कई गंभीर प्रश्न उठाए हैं-घटना के दो माह बाद तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बार-बार शिकायत देने पर भी आवेदन क्यों नहीं लिया गया? निर्दोष परिवार को धमकियाँ क्यों दी गईं? और क्या धन लेकर रिहाई की घटना की जाँच होगी? परिवार ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की माँग करते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा का नहीं, बल्कि व्यवस्था की उस बीमारी का दर्पण है जहाँ पीड़ित ही कटघरे में खड़ा होता है। जब पुलिस वाहन घटनास्थल पर मौजूद हो और फिर भी थाने में "कोई सूचना नहीं" दर्ज हो -तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जब वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद रिहाई के लिए धन लिया जाए- तो यह रिश्वत है, न कि प्रक्रिया। जब दो माह की चुप्पी के बाद अचानक "थाने आओ, वरना लिख देंगे कि आप कार्रवाई नहीं चाहते" जैसे फोन आने लगें-तो यह दबाव है, न्याय नहीं। इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि इस प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच कराएँ-अन्यथा जनता का विश्वास और और कमज़ोर होगा।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा "हेलमेट पहनें-सुरक्षित रहें अभियान" के तहत जन जागरूकता के निरंतर प्रयास जारी...

आदित्य शर्मा

पुलिस कमिश्नर इंदौर की अगुवाई में, अभी तक 25 हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित कर, 3900 से ज्यादा हेलमेट जरूरतमंदों को किये है प्रदाय। सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता हेतु बनाई है एनीमेटेड शॉर्ट फ़िल्में, जो लोगों को करेंगी सड़क सुरक्षा नियम पालन के प्रति प्रेरित।

इंदौर- सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है। इसी कड़ी में आज दिनाँक 31 मार्च 2026 शहर के पलासिया चौराहे पर पुलिस आयुक्त, नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आरके सिंह, पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 25 वाँ 'हेलमेट पहनें-सुरक्षित रहें वृहद जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस कमिशनर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा युवा, बुजुर्ग, जरूरतमंद ऐसे वाहन चालक जिनके पास रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दस्तावेज पूर्ण थे उन्हें हेलमेट प्रदान किए गए। ऐसे वाहन चालकों द्वारा नियमो का उल्लंघन करने पर पहले चालान किया गया फिर सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट भी दिया। ऐसे भी जिम्मेदार दोपहिया वाहन चालक इस अभियान में सम्मिलित हुए जो स्वेच्छा से हेलमेट लगाएं मिले, पुलिस कमिश्नर व अधिकारियों द्वारा ऐसे जिम्मेदार चालको की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए।

सड़क सुरक्षा का महत्व समझाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है, और अभी तक 25 कार्यक्रमों में 3900 से ज्यादा हेलमेट भी वितरित किए गए हैं, ताकि वाहन चालक हादसों की गम्भीरता को समझें और नियमों का पालन करें। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर इंदौर की विशेष उपस्थिति में, सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई शॉर्ट फिल्मों/वीडियो को भी प्रदर्शित किया गया, जिन्हें इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्रिएटर्स के सहयोग से बनाया गया है। ये एनीमेटेड शॉर्ट फिल्म/वीडियो को विभिन्न चौराहों पर व एलइडी स्क्रीन्स और यातायात जागरूकता रथ आदि पर दिखाया जाएगा ताकि लोग इनके जरिए यातायात व सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक हो और उनका पालन करें।

जनसुनवाई में आमजन लेकर आएं अपनी समस्याएं..., पुलिस कमिश्नर इंदौर ने प्रत्येक आवेदक से संवाद कर दिलाया त्वरित समाधान का विश्वास

नागरिकगण, आपसी व पारिवारिक विवाद, पैसों के लेनदेन, फ्रॉड, प्लाट/जमीन की धोखाधड़ी संबंधी विवाद, महिला अपराध संबंधी एवं अन्य पुलिस से संबंधित समस्याओं लेकर आए।

संबंधित अधिकारियों को दिए तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण हेतु दिशा निर्देश ।

आदित्य शर्मा

इंदौर- मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों का निराकरण करनें एवं समस्याओं का त्वरित समाधान करनें के लिए प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती हैं। जिसके तारतम्य में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 31.03.26 को कमिश्नर कार्यालय के सभागार में जनसुनवाई में आमजन की शिकायत एवं समस्याओं को सुना तथा त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दियें। जनसुनवाई के दौरान आज प्रमुख रूप से पारिवारिक/घरेलू विवाद, आपसी विवाद, पैसों के लेनदेन, फाइनेंशियल फ्रॉड, सुनवाई न होने, प्लाट/ जमीन की धोखाधड़ी संबंधी विवाद, महिला अपराध संबंधी एवं अन्य पुलिस से संबंधित समस्याओं के 74 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए । पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक आवेदक के साथ संवाद कर, उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर तत्काल कार्यवाही करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। साथ ही नागरिकों को आश्वस्त किया कि इंदौर पुलिस उनकी सुरक्षा और हितों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर है।

इस दौरान अति पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) इंदौर श्री अमित सिंह एवं सभी ज़ोन के अन्य अधिकारियों ने भी उपस्थित रहकर पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार संबंधित आवेदकों की समस्याओं विस्तार पूर्वक सुन कार्यवाही की गई।

23 देशों में फैला कोरोना का नया वैरिएंट

क्या है Cicada वायरस? भारत पर इसका कितना असर

क्या हम कोरोना से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? शायद नहीं. जब हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है, तभी वायरस का एक नया रूप दुनिया की दहलीज पर दस्तक दे देता है. इस बार चर्चा में है 'Cicada'. अब बात करेंगे सिकाडा की. आपको लग रहा होगा 'सिकाडा' किसी कीड़े का नाम होगा. असल में ये COVID-19 के उस नए वेरिएंट का निकनेम है, जो अमेरिका में जंगल की आग की तरह फैल रहा है. वैज्ञानिक इसे तकनीकी भाषा में BA.3.2 कह रहे हैं. लेकिन क्या ये सिर्फ अमेरिका की समस्या है? बिल्कुल नहीं. खबर है कि भारत में भी INSACOG ने नए वेरिएंट XFG के 163 मामले दर्ज किए हैं. आज के इस विशेष शो में हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि ये 'Cicada' वेरिएंट क्या है और आपको इससे कितना डरने या एहतियात रखने की जरूरत है. सबसे पहले जानते हैं कि ये वेरिएंट कहा से आया है? BA.3.2 असल में Omicron का ही एक वंशज (Descendant) है. ओमिक्रॉन वही वेरिएंट था जिसने 2021 के आखिर में पूरी दुनिया को हिला दिया था. लेकिन BA.3.2 पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले काफी अलग है।

नवंबर 2024 से अफ्रीका से फैलना हुआ शुरू

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके Spike Protein में 70 से 75 आनुवंशिक बदलाव (Genetic Changes) देखे गए हैं. स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो हिस्सा होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसने में मदद करता है. अब चुनौती ये है कि हमारी वैक्सीन इसी स्पाइक प्रोटीन को पहचान कर हमला करना सीखती हैं, लेकिन जब प्रोटीन ही इतना बदल जाए, तो वैक्सीन इसे पहचानने में धोखा खा सकती है. इस वेरिएंट का सफर कहां से शुरू हुआ? शोधकर्ताओं ने सबसे पहले BA.3.2 को नवंबर 2024 में अफ्रीका में पहचाना था. साल 2025 में इसने अपनी वैश्विक यात्रा शुरू की और फरवरी 2026 तक यह दुनिया के 23 देशों में पैर पसार चुका था।

अमेरिका के 29 राज्यों में इसका असर

अमेरिका में इसका पहला मामला जून 2025 में एक यात्री में मिला था. आज स्थिति ये है कि अमेरिका के 29 राज्यों के 'Wastewater' यानी सीवेज के पानी की निगरानी में इस वेरिएंट के निशान मिल रहे हैं. सीवेज मॉनिटरिंग वेरिएंट के फैलाव को समझने का सबसे सटीक तरीका माना जाता है, और आंकड़े बता रहे हैं कि ये वेरिएंट बहुत चुपके से (Under the radar) फैल रहा है. अब सवाल ये है कि ये वेरिएंट अलग क्यों है? इसे एक उदाहरण से समझिए. मान लीजिए आप अपने स्कूल के 25 साल पुराने रियूनियन में जाते हैं. वहां आपको पुराने दोस्त मिलते हैं, लेकिन किसी का वजन बढ़ गया है, किसी ने बाल डाई कर लिए हैं और कोई लेंस लगा रहा है. आप उन्हें पहचान लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा।

क्या BA.3.2 पुराने वेरिएंट्स से ज्यादा खतरनाक? इन पर ज्यादा असर

ठीक यही हमारे इम्यून सिस्टम और इस नए वेरिएंट के साथ हो रहा है. हमारी मौजूदा वैक्सीन JN.1 वंश के वेरिएंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. लेकिन BA.3.2 यानी 'Cicada' हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक 'अजनबी' की तरह है. बदलाव इतने ज्यादा हैं कि शरीर का डिफेंस सिस्टम इसे पहचानने में देरी कर देता है, और इसी देरी का फायदा उठाकर वायरस हमें संक्रमित कर देता है. तो क्या हमें पैनिक करना चाहिए? पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि BA.3.2 पुराने वेरिएंट्स से ज्यादा खतरनाक है या इससे ज्यादा गंभीर बीमारी होती है. लेकिन, संक्रमण की रफ्तार तेज होने का मतलब है कि यह ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है खासकर उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो पहले से फेफड़ों की बीमारी (Chronic Lung Disease) से जूझ रहे हैं या जिन्हें 'Long COVID' की शिकायत है. डेटा बताता है कि आज भी हर 100 में से 3 मामलों में 'Long COVID' के लक्षण विकसित हो रहे हैं. इसलिए, भले ही बीमारी गंभीर न दिखे, लेकिन यह शरीर को लंबे समय के लिए कमजोर कर सकती है।

भारत में अभी स्थिति नियंत्रित, फैलने का डर बरकरार

अब बात करते हैं भारत पर इसका असर है. दरअसल, भारत की जीनोम सीक्वेंसिंग संस्था INSACOG ने हाल ही में बताया है कि देश में XFG वेरिएंट के 163 मामले मिले हैं. यह भी ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड रूप है. ग्लोबल लेवल पर BA.3.2 और भारत में XFG जैसे वेरिएंट्स का उभरना इस बात का संकेत है कि वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के माध्यम से BA.3.2 के प्रसार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हमारी निगरानी प्रणालियों को एक बार फिर सतर्क होने की जरूरत है।

पुरानी वैक्सीन नए खतरे का कर पाएगी मुकाबला?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपकी पुरानी वैक्सीन इस नए खतरे के खिलाफ दीवार बन पाएगी? वर्तमान में हम जो बूस्टर या वैक्सीन ले रहे हैं, वे मुख्य रूप से JN.1 जैसे पुराने वेरिएंट्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं. लेकिन वैज्ञानिकों की मानें तो BA.3.2 यानी 'Cicada' हमारे शरीर के लिए एक 'कम्पलीट स्ट्रेंजर' (Complete Stranger) की तरह है. पल्मोनरी एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि चूंकि इस वेरिएंट का हुलिया पिछले वायरस से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इसे उतनी तेजी से नहीं पहचान पाएगा, जितनी तेजी से इसे पहचानना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन बेकार है- वो अब भी अस्पताल जाने की नौबत और मौत के खतरे से बचाती है. लेकिन इस नए वेरिएंट के साथ 'परफेक्ट मैच' न होने के कारण यह वायरस हमारे शरीर के सुरक्षा कवच में सेंध लगाने में कामयाब हो रहा है।

कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम 'Cicada' क्यों पड़ा?

यहां एक और दिलचस्प तथ्य है- इस वेरिएंट का नाम 'Cicada' क्यों पड़ा? दरअसल, सिकाडा एक ऐसा कीड़ा है जो सालों तक जमीन के नीचे छिपा रहता है और फिर अचानक बाहर निकलकर सबको चौंका देता है. ठीक वैसे ही, BA.3.2 भी साल 2024 के अंत से 'अंडर द राडार' यानी वैज्ञानिकों की नजरों से बचकर खामोशी से फैल रहा था. सबसे चौंकाने वाली बात इसके स्पाइक प्रोटीन में मौजूद 70 से 75 म्यूटेशन हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह वायरस के सामान्य विकास से कहीं ज्यादा बड़ी छलांग है. यह विज्ञान के लिए किसी पहेली से कम नहीं है कि कैसे एक वायरस ने अपना हुलिया इतना बदल लिया कि वह अब हमारी पुरानी वैक्सीन को चकमा देने की पूरी ताकत रखता है।

सीवेज के पानी की जांच से 'Cicada' वेरिएंट की पहचान

इस अदृश्य खतरे को पहचानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा 'जासूसी' तरीका अपनाया है-'वेस्टवॉटर मॉनिटरिंग' यानी सीवेज के पानी की जांच. अमेरिका के 29 राज्यों में जब मरीजों की अस्पतालों में भीड़ लगनी शुरू भी नहीं हुई थी, तब वहां के गंदे पानी के सैंपल्स में इस 'Cicada' वेरिएंट के निशान मिल गए थे. यह तकनीक हमें बीमारी के फैलने से हफ्तों पहले आगाह कर देती है. हालांकि, चिंता की बात यह है कि साल 2022 के बाद से दुनिया भर में इस तरह के डेटा शेयरिंग सिस्टम में कमी आई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम अपनी इस 'बायोलॉजिकल जासूसी' को धीमा करेंगे, तो वायरस के अगले बड़े हमले को समय रहते भांपना नामुमकिन हो जाएगा.

कोरोना के इस वेरिएंट से कैसे बचे?

तो बचाव का रास्ता क्या है? डॉक्टर्स चार आसान सलाह देते हैं: हाथ धोना न छोड़ें, इससे सांस संबंधी इन्फेक्शन का खतरा 21% तक कम हो जाता है. अगर तबीयत खराब लगे, तो घर पर रहें. भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें और खुली हवा में वक्त बिताएं. और सबसे जरूरी, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें. कोरोना गया नहीं है, वो बस बदल रहा है. और उससे लड़ने का क्लियर कट तरीका है – सतर्कता और सही जानकारी।

निर्माणाधीन टनल में जोरदार धमाका, कुछ की मिनटों में मच गया हड़कंप 4 मजदूरों की गई जान

दक्षिण-पश्चिम चीन के चोंगकिंग (Chongqing) निकाय क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक निर्माणाधीन सुरंग में भीषण विस्फोट होने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 9 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार सुबह इस त्रासदी की पुष्टि की है।

कैसे हुआ हादसा?

यह विस्फोट सोमवार दोपहर उस समय हुआ जब हुबेई और सिचुआन प्रांतों को जोड़ने वाले एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सुरंग बनाई जा रही थी। वानझोउ जिला परिवहन आयोग के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि निर्माण स्थल पर मौजूद मजदूर इसकी चपेट में आ गए। शुरुआत में एक व्यक्ति लापता था और 12 घायलों की खबर थी। एजेंसी 'शिन्हुआ' के मुताबिक सोमवार आधी रात तक बचाव दल ने लापता व्यक्ति का शव मलबे से निकाल लिया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान तीन और घायलों ने दम तोड़ दिया।

विस्फोट का मुख्य कारण: ज्वलनशील गैस

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुरंग के भीतर ज्वलनशील गैस (Flammable Gas) जमा हो गई थी, जिसके कारण यह ब्लास्ट हुआ। हालांकि अभी विस्तृत तकनीकी जांच होना बाकी है।

वर्तमान स्थिति

हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है और निर्माण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। घायलों का इलाज जारी है और विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही बरती गई थी।

"अस्तित्व और पहचान की जंग लड़ता एक समुदाय"

हम प्रायः समाज को कोटियों यानी वर्गों या श्रेणियों में बांटकर देखने के आदी हो गए हैं। दलित, जनजाति, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम जैसी अनेक कोटियां समाज को देखने के हमारे नजरिये पर हावी रहती हैं। हम अक्सर समाज को इन्हीं स्थिर वर्गों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं कि सामाजिक वास्तविकता इन्हीं सीमाओं के भीतर पूरी तरह समाहित हो जाती है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इन कोटियों के बीच भी अनेक ऐसे सामाजिक समूह मौजूद हो सकते हैं, जो इन निर्धारित श्रेणियों में पूरी तरह समाहित नहीं होते। हम यह भी समझना नहीं चाहते कि ये कोटियां हमेशा कठोर और स्थायी नहीं होतीं, बल्कि कई बार लचीली और परिवर्तनशील भी होती हैं। सामाजिक जीवन की जटिलता कई बार इन कोटियों की सीमाओं को चुनौती देती है।

वास्तव में समाज की संरचना इतनी सरल नहीं होती कि उसे केवल कुछ तयशुदा श्रेणियों में पूरी तरह समझ लिया जाए। दलित एवं जनजाति दो ऐसी कोटियां हैं, जिन्हें हमारी राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था ने विशेष रूप से निर्मित किया है। औपनिवेशिक जनगणना के दौरान पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोटियां बनाकर अनेक विविध सामाजिक समूहों को उनमें सम्मिलित कर दिया गया। औपनिवेशिक शासन की रणनीति समाज को अलग-अलग वर्गों में बांटकर शासन को सरल बनाना और कई बार विभाजन की रेखाएं खींचना भी था। इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे समुदाय बने रहे, जो इन श्रेणियों में रखे जाने के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान को अलग ढंग से समझते एवं विश्लेषित करते रहे।

उदाहरण के लिए, कई दलित जातियां दलित कोटि में दर्ज होने के बावजूद अपने आपको जनजातीय विशेषताओं से युक्त मानती रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले मुसहर समुदाय को प्रशासनिक रूप से दलित कोटि में दर्ज किया गया है, किंतु अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मछवि में वे अपने आपको कई जनजातीय विशेषताओं से युक्त मानते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में कोल और खरवार जैसे समुदायों को प्रशासनिक दृष्टि से अनुसूचित जाति में रखा गया है, जिन्हें कई स्थानों पर जनजातीय माना जाता है। उनके दैनिक जीवन, कर्मकांड, पूजा-पद्धति और सांस्कृतिक व्यवहार में वैसे जनजातीय संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यह स्थिति दर्शाती है कि सामाजिक वास्तविकता प्रशासनिक वर्गीकरण से कहीं अधिक जटिल और बहुआयामी होती है।

इन दोनों कोटियों के बीच भी कई ऐसे सामाजिक समूह मौजूद हैं, जो न पूरी तरह इधर के हैं और न पूरी तरह उधर के। वे सामाजिक संरचना में एक प्रकार की मध्यवर्ती स्थिति में रहते हैं। ऐसे समूहों को सिद्धांतकार 'बीच के समूह', 'बीच की अस्मिता वाले समुदाय' अथवा 'लिमिनल आइडेंटिटी' वाले समूह कहते हैं। ये समुदाय समाज की मुख्यधारा में होते हुए भी कई बार पहचान और अधिकार के स्तर पर अस्पष्ट स्थिति में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक समूह है-वनटांगिया समुदाय, जो मुख्यतः महाराजगंज एवं गोरखपुर क्षेत्र के जंगलों में बसता है। इनका मुख्य कार्य जंगलों में विशेष पद्धति से साखू के पेड़ लगाना था। यह स्पष्ट नहीं है कि ये समुदाय कब और कैसे इस क्षेत्र में आए, परंतु इतना निश्चित है कि अंग्रेजी शासन के समय से ही ये इस कार्य से जुड़े रहे हैं। लंबे समय तक यह समुदाय प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। लंबे समय तक उनकी जमीन भी उनकी अपनी नहीं थी। जिन बस्तियों में वे रहते थे, उन्हें वैध मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्हें मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ व्यवस्थित रूप से मिल पाता था। जब किसी समुदाय की पहचान और निवास का वैध आधार ही न हो, तब विकास की योजनाएं भी उन तक पहुंच नहीं पातीं। योगी आदित्यनाथ ने संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ी तब वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला और उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर सरकारी आवास योजनाएं, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य कल्याणकारी नीतियां उन तक पहुंचने लगीं। इस प्रकार वे धीरे-धीरे विकास की धारा से जुड़ सके और उन्हें लोकतांत्रिक सम्मान भी प्राप्त होने लगा। वास्तव में समाज में ऐसे कई समूह हैं, जो दो स्थापित कोटियों के बीच स्थित हैं और जिनकी पहचान पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। किसी भी संवेदनशील प्रशासन का नैतिक दायित्व है कि ऐसे उपेक्षित और भटके हुए समुदायों की पहचान करे और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़े। इसके लिए आवश्यक है कि हम केवल बनी-बनाई कोटियों के दबाव में न रहें, बल्कि नए सामाजिक अनुसंधानों और अध्ययन के माध्यम से समाज की जटिल वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करें। राजनीतिज्ञों को भी आगे आकर 'उपेक्षितो में भी उपेक्षित' समूहों के पहचान, विकास एवं सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसके लिए प्रशासन, नीतियों और ज्ञान की नई दृष्टि विकसित करनी होगी, ताकि समाज के ऐसे अदृश्य या उपेक्षित समूहों को पहचान, सम्मान और विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें। नहीं तो ऐसे समूह विकास की धारा में छूटे ही रह जाएंगे और इन समूहों तक विकास एवं जनतांत्रिक चेतना का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

डिजिटल दौर में नई शुरुआत

जनगणना से बदलेगी देश की सामाजिक तस्वीर

अंततः वह समय आ ही गया है जब लंबे इंतजार के बाद देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वर्ष 2021 में प्रस्तावित यह महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न कारणों से टलता रहा, लेकिन अब इसके शुभारंभ के साथ एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। इस बार की जनगणना कई मायनों में विशेष है, क्योंकि यह न केवल तकनीकी रूप से आधुनिक होगी, बल्कि इसके माध्यम से देश की सामाजिक, आर्थिक और जातीय संरचना की विस्तृत और अद्यतन तस्वीर भी सामने आएगी।

इस जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल स्वरूप है। पहली बार पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रिया को पीछे छोड़ते हुए मोबाइल एप, वेब पोर्टल और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल आंकड़ों के संग्रहण की गति तेज होगी, बल्कि त्रुटियों की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। डिजिटल माध्यम से प्राप्त जानकारी सीधे सर्वर पर अपलोड होगी, जिससे डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित होंगी। यह बदलाव प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है।

जनगणना को इस बार दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है, जिससे कार्य को अधिक व्यवस्थित और सटीक ढंग से संपन्न किया जा सके। पहले चरण में मकानों और आवासीय सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इस तरह की संरचना से डेटा संग्रहण अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित होगा, जिससे नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बार आम नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का विकल्प भी दिया जाएगा। यह व्यवस्था नागरिकों को प्रक्रिया में सीधे शामिल करती है और पारदर्शिता को बढ़ाती है। हालांकि इसके साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि नागरिकों को अपनी जानकारी पूरी ईमानदारी और सावधानी के साथ दर्ज करनी होगी। जनगणना आयुक्त द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे लोगों के बीच विश्वास बना रहेगा। इस जनगणना की ऐतिहासिक महत्ता केवल इसके डिजिटल स्वरूप तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाएगा। यह कदम देश की सामाजिक संरचना को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे विभिन्न जातीय समूहों की वास्तविक स्थिति, उनकी जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्तर की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1931 के बाद से देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में वर्तमान समय में विभिन्न जातियों द्वारा किए जा रहे दावों की सत्यता पर प्रश्नचिह्न लगा रहता है। इस जनगणना के माध्यम से इन दावों की वास्तविकता सामने आएगी और एक सटीक तस्वीर उभरकर सामने आएगी। यह न केवल शोध और विश्लेषण के लिए उपयोगी होगी, बल्कि सरकार को नीतियां बनाने में भी महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करेगी। हालांकि, इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। जातिगत आंकड़ों के सार्वजनिक होने से यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह जानकारी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल न होने लगे।

मुख्यमंत्री के दौरे में लापरवाही पड़ी भारी, ड्यूटी से नदारद पर टीआई सस्पेंड

इंदौर। इंदौर में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसमें वीआईपी ड्यूटी में तैनात थाना प्रभारी के अनुपस्थित रहने पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।दरअसल इंदौर में 29 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर दौरे पर थे, जहां यातायात व्यवस्था के तहत बापट चौराहे पर टीआई राहुल सिंह राजपूत की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन निर्धारित स्थान पर वे समय पर मौजूद नहीं मिले। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी पहले भी लापरवाही के मामलों में कार्रवाई झेल चुके हैं। ऐसे में वीआईपी ड्यूटी जैसे संवेदनशील मौके पर गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है और सभी अधिकारियों को ड्यूटी के प्रति सख्त रहने के निर्देश दिए गए हैं।

एक अप्रैल का महंगाई पैकेज, नए नियम से घर दुकान, बिजली, टोल और एटीएम डालेगा जेब पर असर

भोपालः नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से घर और जमीन खरीदना महंगा होगा, बिजली बिल बढ़ेगा, हाईवे पर सफर के लिए ज्यादा टोल देना पड़ेगा और एटीएम से पैसे निकालना भी महंगा हो जाएगा. इसके साथ ही रेलवे रिजर्वेशन के नियम बदलेंगे. कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू होंगे और आयकर व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है. इन फैसलों का सीधा असर आम आदमी के मासिक बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा।

घर और जमीन खरीदना होगा महंगा

नए वित्तीय वर्ष के साथ मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा. सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में औसतन करीब 16 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इससे रजिस्ट्री कराने की लागत बढ़ जाएगी. प्रदेश में लगभग 65 हजार स्थानों पर नई गाइडलाइन लागू की जा रही है. इसके अलावा पक्के मकानों के निर्माण की लागत भी करीब 1000 रुपए प्रति वर्गमीटर बढ़ा दी गई है. ऐसे में घर या जमीन खरीदने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी. प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ जारी किया है. इसके तहत बिजली की दरों में औसतन करीब 4.80 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. नई दरों का असर प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. हालांकि 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी गई है. लेकिन अधिक खपत करने वालों के बिल में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. उदाहरण के तौर पर 200 यूनिट बिजली खपत पर पिछले साल की तुलना में करीब 80 रुपए ज्यादा और 400 यूनिट खपत पर 150 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।

हाईवे पर सफर करना भी महंगा

1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर भी महंगा हो जाएगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में करीब 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी लागू करने का फैसला किया है. इसका असर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख हाईवे पर पड़ेगा. इससे जबलपुर से नागपुर, रायपुर, प्रयागराज और भोपाल की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को हर टोल प्लाजा पर ज्यादा भुगतान करना होगा. वहीं कार चालकों को कई टोल प्लाजा पर 5 से 10 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. इसके अलावा फास्टैग से मिलने वाले वार्षिक पास की कीमत में भी लगभग 75 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।

एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा

नए वित्तीय वर्ष में बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम का उपयोग भी महंगा हो जाएगा. पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद अब अतिरिक्त निकासी पर ग्राहकों को पहले से ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा. नई व्यवस्था के तहत हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर करीब 23 रुपए तक शुल्क और उस पर लागू टैक्स देना होगा. इससे बार-बार एटीएम से पैसे निकालने वाले ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

रेलवे रिजर्वेशन नियम बदले

रेलवे यात्रियों के लिए भी 1 अप्रैल से रिजर्वेशन और टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं. नए नियमों के अनुसार ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा. पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी. वहीं 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर किराए का लगभग 50 प्रतिशत और 24 से 72 घंटे पहले रद्द करने पर 25 प्रतिशत कटौती के बाद शेष राशि लौटाई जाएगी. इसके अलावा यात्री ट्रेन के प्रस्थान से आधा घंटा पहले तक क्लास अपग्रेड कराने की सुविधा भी ले सकेंगे.

कचरा अलग नहीं किया तो जुर्माना

शहरों में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1 अप्रैल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 लागू किए जा रहे हैं. इसके तहत हर घर को कचरे को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटना अनिवार्य होगा. इनमें गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक कचरा शामिल है. यदि कोई घर, होटल या संस्था कचरे का पृथक्करण नहीं करती है तो नगर निगम सीधे जुर्माना लगा सकेगा. बड़ी सोसायटी, होटल और अस्पताल जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने स्तर पर कचरे का निपटान भी करना होगा।

आयकर प्रणाली में भी बदलाव

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए भी नए बदलाव लागू किए जा रहे हैं. अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे शब्दों की जगह 'टैक्स ईयर' शब्द का उपयोग किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और समझने में आसान बनाना है. डिजिटल माध्यमों से टैक्स भुगतान और रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो सके।

नगर निगम कर में छूट खत्म होने का असर

वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च तक संपत्तिकर और जल उपभोक्ता प्रभार जमा करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट दी गई है. लेकिन 1 अप्रैल के बाद यह राहत खत्म हो जाएगी. नगर निगम के अनुसार स्वयं उपयोग वाली संपत्तियों पर अब दोगुना भुगतान करना पड़ सकता है और पहले मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट भी समाप्त हो जाएगी. ऐसे में समय पर कर जमा नहीं करने वाले लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

इंदौर से रेलवे को पार्किंग से सालाना आय होती है एक करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक की

इंदौर। पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य भाजपा नेता ने इंदौर रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड से रेलवे को प्रतिवर्ष एक करोड रुपए से अधिक की आय होती है ।

वर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 तक डॉ अंबेडकर नगर (महू), लक्ष्मीबाई नगर,राऊ, राजेंद्र नगर से पार्किंग स्टैंड से आय की प्राप्त जानकारी अनुसार इंदौर से 1,87,15,550/- डॉ अंबेडकर नगर से 4,87,747/- रुपए लक्ष्मीबाई नगर से 3,94,375/- रु तथा राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग से 1,00,232/- रु यानी कि कुल पार्किंग से आए 1,95,97,672/- रु की हुई है। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 तक इंदौर रेलवे स्टेशन के कैटरिंग स्टॉल से उन 50,61,294/-,बुक स्टॉल से 18,405/- रुपए, मिल्क पार्लर से 5,65,860/-, खानपान ट्राली से 9,99,380/- रुपए एवं पार्सल लगेज से 8,72,06,742/- की वार्षिक आय रेलवे को होती है। वही इंदौर रेलवे स्टेशन के शयन कक्ष से 37,97,900/- और डॉ अंबेडकर नगर (महू) के

शयनकक्ष से 6,375/-, 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक आय अर्जन रेलवे को हुई है। लक्ष्मीबाई नगर, राऊ एवं राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर शयनकक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

लाल अस्पताल को एंटीरैबीज वैक्सीन सेंटर का ब्रांड बनाने वाले डाक्टर की 23 साल बाद विदाई

इंदौर। शहर के सरकारी लाल अस्पताल को एंटीरैबीज वैक्सीन सेंटर का ब्रांड बनाने वाले अधीक्षक डाक्टर शर्मा की सालों की शासकीय सेवाओं के दौरान आज लाल अस्पताल से 23 साल बाद सेवानिवृत्ति मतलब विदाई होने जा रही है। मौजूदा स्टाफ और हेल्थ विभाग के अनुसार डाक्टर शर्मा के सेवा समर्पण भाव के चलते लाल अस्पताल मध्य प्रदेश का ऐसा नम्बर वन हास्पिटल बन चुका है, जहां 365 दिन सुबह 9 से रात 8 बजे तक एंटीरैबीज वैक्सीन और एंटीइंफेक्शन टिटनेस इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अधीक्षक डाक्टर शर्मा के कार्यकाल में 10 लाख से ज्यादा डॉग्स बाइट पीड़ितों को एंटीरैबीज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी वजह से शहर से लेकर इन्दौर जिले में लाल अस्पताल की पहचान कुत्तों के काटने के बाद इंजेक्शन लगाने वाले अस्पताल की बन चुकी है। हेल्थ विभाग के विष्णु चौधरी के अनुसार राखी हो, दिवाली हो, ईद हो या होली के अलावा कोई भी बड़ा त्योहार क्यों न हो, मगर लाल अस्पताल में कभी छुट्टी नहीं रही। यहां 365 दिन एंटीरैबीज के इंजेक्शन लगते हैं। एक समय ऐसा भी आया किसी इमरजेंसी की चलते एंटीरैबीज वैक्सीन की सप्लाय थम गई।

सहज स्वभाव में स्थित व्यक्ति सदैव विजयी होता है : श्री माताजी

सहजयोग श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा प्रतिस्थापित एक जीवंत वैज्ञानिक पद्धति है। सहजयोग कोई यौगिक अथवा शारीरिक क्रिया नहीं है वरन् सहजता से जीवन को जीना है। सहज रूप से जब हमारा योग अर्थात् जुड़ना परम शक्ति से हो जाता है तब हम सहजयोगी हो जाते हैं। सहजयोग कोई नई विचारधारा, संप्रदाय अथवा धर्म नहीं है यह तो संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखने वाला परमात्मा का यंत्र है। मनुष्य को परमशक्ति द्वारा बुद्धि प्रदान कर विचारों की स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसी बुद्धि ने उसे असहज बना दिया। मानव जाति को इस भटकाव से बचाने के लिए अनेक अवतार, गुरु, व संत इस संसार में

समय समय पर परमात्मा की इच्छा से अवतरित हुए और सभी ने सहजता की ही बात की व सहज जीवन को ही जिया। भारत में अनेकानेक ऐसे संत हुए हैं जो अपने गुणों के द्वारा देव तुल्य हो गए। ऐसे ही संत कबीर दास जी का नाम संतों की अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। जीवन की सहजता का वर्णन संत कबीर दास जी ने अपने दोहे में इस प्रकार किया है कि, सहज सहज सब कोई कहै,सहज न चीन्हें कोय |

जिन सहजै विषया तजै, सहज कहावै सोय |

अर्थात् सहज - सहज सब कहते हैं, परन्तु उसे समझते नहीं जिन्होंने सहजरूप से विषय - वासनाओं का परित्याग कर दिया है, उनकी निर्विषय- स्थिति ही सहज कहलाती है। कबीर दास जी द्वारा वर्णित इसी सहजता की प्राप्ति सहजयोग में श्री माताजी के सानिध्य व कृपा में आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति के पश्चात् होती है। हम अपने सहज स्वभाव में स्थित रहने लगते हैं व समस्त दुश्चिंताओं से शारीरिक कष्टों से मुक्ति संभव हो जाती है। इस का वर्णन करते हुए श्री माताजी ने कहा है कि, "जब आप भगवान के साम्राज्य में खड़े होते हैं खुशी के साम्राज्य में तो हर हाल में तुम राजा और रानी बनते हो। कोई भी आपको खरीद नहीं सकता या आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब कुछ जीत लेते हैं।" सहजयोग ध्यान का आनंद और अनगिनत लाभ लेने हेतु अपने नज़दीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की मूल्यांकन प्रणाली में बेहतर कार्य करने वाले एसीपी व थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों को मिला अच्छे कार्य का ईनाम

आदित्य शर्मा

पुलिस कमिश्नर इंदौर ने पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व शील्ड से पुरस्कृत कर, सभी को ऐसे ही बेहतर कार्य के लिए किया प्रोत्साहित। मूल्यांकन प्रणाली में विभिन्न पैरामीटर्स पर सभी एसीपी कार्यालयों में बेहतर परफॉर्मेंस कर माह जनवरी में एसीपी हीरानगर नगर तथा माह फरवरी में एसीपी खजराना ने पाया है प्रथम स्थान। नगरीय इंदौर के सभी थानों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर माह जनवरी में थाना विजय नगर तथा माह फरवरी में थाना बाणगंगा रहा है प्रथम।

इंदौर शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण व बेहतर पुलिसिंग हेतु पुलिस के कार्य निष्पादन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुखी बनाए जाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पुलिस थानों व एसीपी कार्यालयों के कार्य की एक मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली माह जनवरी से प्रारंभ की गई है, जिसमें विभिन्न मापदंडों पर प्रत्येक ज़ोन में पुलिस थानों व एसीपी के कार्यों की समीक्षा कर उन मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जा रहा है।

उक्त मूल्यांकन में विभिन्न पैरामीटर्स पर सभी 12 एसीपी कार्यालयों में बेहतर परफॉर्मेंस कर माह जनवरी में एसीपी हीरानगर नगर तथा माह फरवरी में एसीपी

खजराना प्रथम स्थान पर रहे हैं। इसी प्रकार नगरीय इंदौर के सभी थानों में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर माह जनवरी में थाना विजय नगर तथा माह फरवरी में थाना बाणगंगा प्रथम स्थान पर रहा। बेहतर कार्य करने वाले एसीपी व थाना प्रभारियों सहित पुलिस कर्मियों की टीम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 31 मार्च 2026 को पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा एसीपी हीरानगर श्रीमती रूबिना मिजवानी, एसीपी खजराना श्री कुंदन मंडलोई व थाना प्रभारी विजय नगर, थाना प्रभारी बाणगंगा और दोनों थानों के पुलिस कर्मियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत कर, उनके कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर सभी को पुरस्कृत करते हुए पुलिस कमिश्नर इंदौर ने कहा कि उक्त मूल्यांकन प्रणाली के तहत पुलिस थानों व एसीपी द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा संबंधित ज़ोन के डीसीपी की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा निर्धारित मापदंडों पर किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग वरिष्ठ स्तर पर की जाती है, जिसके आधार पर पूरे इंदौर कमिश्नरेट के सभी 32 थानों व 12 सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालयों के कार्य निष्पादन, जनसंतुष्टि और आमजन के हित में किये जा रहे नवाचारों आदि पैरामीटर्स के आधार पर, बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले एसीपी व पुलिस थानों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जा रहा है, वही कमजोर/सबसे औसत परफॉर्मेंस के साथ निचले क्रम में आने वाले एसीपी व थानों को उचित प्रशिक्षण व विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है ताकि वह अपनी कार्य प्रणाली में और बेहतर सुधार ला सके।

आत्मानुभूति जीवन में सबसे सुन्दर अवस्था है : श्री माताजी

श्री माताजी द्वारा प्रतिस्थापित सहजयोग ध्यान, कुंडलिनी जागरण तथा आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति पर आधारित है। परंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि आत्मसाक्षात्कार वस्तुतः क्या है तथा इसे पाना क्यों आवश्यक है? साथ ही जिज्ञासा यह भी उठती है की आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति के पश्चात हमें क्या उपलब्धि हासिल होती है। कुंडलिनी जागरण द्वारा आत्मसाक्षात्कार अर्थात् आत्मबोध के विषय में श्री माताजी ने अपनी अमृतवाणी में वर्णित किया है कि, "जब आपको आत्मबोध हो जाता है, तो आपका पूरा तन, मन, सब कुछ एकीकृत हो जाता है और आप जो कुछ भी करते हैं वह आनंद प्रवाहित करता है। अब यह सब आपके लिए बहुत विलक्षण है। मैं जानती हूं कि यह आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है.... यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह एकमात्र चीज़ है जिसे आपको हासिल करना है। बेकार के चमत्कारों में न जाएं। अपनी आत्मा के चमत्कारों को मांगें। जब आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप कितना सुन्दर महसूस करते हैं, और कितनी सुन्दरता से आप इसे कार्यान्वित करते हैं, क्योंकि आपने अपनी पूर्णता को पा लिया है, आपको अपनी मंजिल मिल गई है, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं।" (17 जुलाई 1980) आत्मतत्व की प्राप्ति के सवाल पर अधिकांशतः यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह महान, मनीषियों के लिए तो संभव है परन्तु क्या भौतिक जगत में रहते हुए साधारण मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान में श्री माताजी की अनुकम्पा से यह सर्वसुलभ है तथा अत्यंत सहज है। सर्वधर्म व संपूर्ण विश्व के लाखों सामान्य व्यक्तियों ने इसे प्राप्त किया है। आप भी इस आनंद को सहज में ही पा सकते हैं। सहजयोग से संबंधित जानकारी निम्न साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। यह पूर्णतया निशुल्क है। टोल फ्री नं – 1800 2700 800

CM ममता को टक्कर देने वाले BJP प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी पर है 25 केस, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी लगा है आरोप

बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने अपने शपथपत्र में बताया कि उनके खिलाफ कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से टीएमसी से ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। पिछले विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया था। वहीं अब भवानीपुर में भी दोनों नेता आमने-सामने हैं। सुवेंदु इस बार भी ममता को हराने की बात कह रहे हैं।

सुवेंदु अधिकारी पर क्या-क्या लगा आरोप हत्या का प्रयास आपराधिक धमकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य दंगा और विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना वीडियो के जरिए नफरत फैलाने और जातिसूचक टिप्पणी यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग मानहानि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है।

शपथ पत्र में क्या बताया

अपने शपथपत्र में अधिकारी ने अपना पेशा राजनेता और व्यवसायी बताया है। उनकी आय के स्त्रोतों में विधायक वेतन, सांसद पेंशन और व्यवसाय शामिल हैं। अधिकारी 2009 और 2014 में लोकसभा सांसद रह चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस सरकार में परिवहन और सिंचाई जैसे विभाग भी संभाल चुके हैं। नंदीग्राम से दाखिल ताजा नामांकन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि चल-अचल संपत्ति का मूल्य 83,20,702 रुपये बताया गया है।

क्या बोले सुवेंदु अधिकारी

नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी ममता हारेंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से बीजेपी को भवानीपुर में फायदा होगा।

ओडिशा में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद UP में बवाल, लखनऊ से मुरादाबाद तक सड़क पर उतरे किसान

किसान नेता राकेश टिकैत की ओडिशा में गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है. सोमवार, 30 मार्च को जैसे ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, भारतीय किसान यूनियन (BKU) के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर गए. राजधानी लखनऊ में किसानों ने गिरफ्तारी के विरोध में हजरतगंज थाने का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन

राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का असर पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में भी देखने को मिला. गुस्साए किसानों ने मुरादाबाद के अलग-अलग थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और टिकैत की रिहाई की मांग कर रहे हैं. सोमवार से ही बड़ी संख्या में किसान यहां इकजुट होना शुरू हो गए और दरी बिछाकर बैठ गए. किसानों का कहना है कि राकेश टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर ओडिशा में चल रहे आंदोलन को मजबूत करने जा रहे थे. लेकिन, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है।

राकेश टिकैत को रिहा करने की मांग

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ कहा कि जब तक टिकैत को सम्मान के साथ रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. राकेश टिकैत की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है. यह किसानों की आवाज दबाने की कोशिश है। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, हमारा धरना जारी रहेगा मेरठ और बिजनौर में भी भाकियू के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो और थाना घेराव का बिगुल फूँक दिया है. मवाना में किसानों ने सीओ दफ़्तर का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की उन्होंने कहा कि जब तक टिकैत को रिहा नहीं किया जाएगा वो यहां से हटेंगे नहीं।

मुस्लिम-दलित कार्ड पर कांग्रेस का बड़ा दांव!

बंगाल में क्या Mamata Banerjee का खेल बिगड़ेगा या बीजेपी को लगेगा झटका?

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी 'एकला चलो' की रणनीति अपनाई है। प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से 284 पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में कांग्रेस ने कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया है। पार्टी ने बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को टिकट दिया है। दरअसल, इस बार कांग्रेस ने गठबंधन से दूरी बनाते हुए अपने दम पर खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने पर फोकस किया है।

कांग्रेस ने 64 मुसलमानों को दिया टिकट

कांग्रेस की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा सोशल इंजीनियरिंग है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 64 मुस्लिम, 68 दलित, 16 अनुसूचित जनजाति और 42 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। पहली सूची के मुताबिक कांग्रेस ने मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर फोकस किया है, यह ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के लिए भी मुसीबत बन सकता है।

राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम बाहुल इलाके की सीट मालदा और मुर्शिदाबाद में भी प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम बहुल सीटों में से कुछ सीटों पर जीतकर वापसी की अपनी नींव रख सकती है। हालांकि, यहां मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और अन्य दल भी मैदान में हैं, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा संभव है।

TMC का बिगड़ सकता खेल

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक से ही सत्ता में वापसी की थी।

मुख्यमंत्री सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से होंगे रूबरू

इंदौर। स्कूलों की छुट्टियों का आज अंतिम दिन है। कल से सभी विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचेंगे व प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और सरकार की ओर से स्कूल चले हम अभियान शुरू होगा। स्कूलों में प्रवेश उत्सव के लिए विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत करेंगे और फूलमालाएं भी पहनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव विद्यार्थियों से सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। मध्यप्रदेश के 92 हजार सरकारी स्कूलों में कल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों में तकरीबन 85 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनकी कक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल चले हम अभियान शैक्षणिक सत्र के साथ ही शुरू किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को कक्षा और स्कूल के प्रति आकर्षण और शैक्षणिक गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। अभिभावकों से संवाद भी किया जाएगा और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने को लेकर शिक्षकों को अलग-अलग जवाबदारियां भी दी गई हैं।स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि शुरुआत से ही स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बेहतर संचालित हो सके। जिला शिक्षा अधिकारी शांतस्वामी भार्गव ने बताया कि इंदौर में प्रवेश उत्सव सभी सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा।